रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225319
SG-DL-E-20022021-225319

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/ माघ 30, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 332
No. 61] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942 [N. C. T. D. No. 332

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

सं. फा. 6/19/2020–न्याय/अधी.विधि./231-237.—अद्यतन यथासं"ोधित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 12 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामं"ा से श्री विरेन्द्र कुमार खरटा को उनके द्वारा कार्यभार सम्भालने की तिथि से, स्थायी पद पर, योग्यता के क्रम में अस्थायी रूप से दो वर्षों की परिवीक्षा पर, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त करते हैं।

2. ये नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर हैं तथा अभ्यर्थियों के चरित्र पूर्ववृत्तों के सत्यापन तथा जाति/दिव्यांग प्रमाण पत्र जहां लागू हो, के अनुसार होगी । यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग श्रेणी, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन की जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपर्युक्त नियुक्ति अद्यतन तिथि तक तथा समय–समय पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी ।

4. पद का वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070 रुपये (पूर्व संशोधित) + सामान्य भत्ते जैसा समय–समय पर इस संबंध में लागू हो के अनुसार है।

5. उपर्युक्त नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 10113/2015 – मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य, और रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 8132/2020 – राहुल शर्मा बनाम महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य के फैसलों के आधीन होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 19th February, 2021

No. F. 6/19/2020-Judl./Suptlaw/231-237.—In pursuance of the provisions of Rule 12 of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Mr. Virender Kumar Kharta as member of the Delhi Higher Judicial Service against permanent posts in temporary capacity in order of merit on a probation period of two years w.e.f. the date he assume the charge of his office.

2. The above appointment is on purely provisional basis, and subject to the verification of character and antecedents of the candidate from the concerned authorities and verification of his caste certificate/PH category certificate, where ever applicable. If the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe or Physically Handicapped category, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.

3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Higher Judicial Service from time to time.

4. The post carries the time-scale of pay of members of the Delhi Higher Judicial Service Rs.51550-1230-58930-1380-63070 (pre-revised) plus allowances as admissible under the Rules.

5. The above appointment shall be subject to the final outcome of WPC No.10113/2015 titled “Mukesh Kumar & Ors. VS Registrar General, Delhi High Court & Ors.” and WPC No.8132/2020 titled “Rahul Sharma Vs. Registrar General, High Court of Delhi’’ pending in Hon’ble High Court of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & LA)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.20 17:29:53 +05'30'